GUJHIN/2021/80146

Email : satyawadimanch@gmail.com

सत्य के साथ

सत्यवादी मंच

हिन्दी साप्ताहिक

प्रधान संपादक -विनोद कुलकर्णी
98251 85093

email ID- Vinodkulkarni2011@gmail.com

मार्केटिंग: जीज्ञेश चावडा: 9824914993

● वर्ष : 05 ● अंक : 12 ● (सूरत) ● दिनांक : 09/04/2025 बुधवार, :245, आशिर्वाद टाउन शिप-1, बमरोली रोड, उधना, जिला-सूरत,गुजरात। पृष्ठ-4, मूल्य 5/ रुपए

YEAR-05, ISSUE-12 (SURAT) DATE-09/04/2025 WEDNESDAY, 245, AASHIRWAD TOWN SHIP-1, BAMROLI ROAD, UDHANA, DIST-SURAT, GUJARAT. PAGE-04, Rs.05/- Only

आतंकवाद को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए

शाह ने जम्मू-कश्मीर में विकास, वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की

जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी संगठन हुर्रियत को मंगलवार को झटका लगा

जम्मू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में जारी विकास परियोजनाओं और वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को दो बैठकों की अध्यक्षता की।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज (मंगलवार को) जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। मोदी सरकार एक विकसित जम्मू-कश्मीर के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से विकास और कल्याणकारी पहलों के माध्यम से हर नागरिक के लिए समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। जम्मू-कश्मीर हर क्षेत्र में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

शाह ने एक और पोस्ट में कहा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू-कश्मीर के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मोदी सरकार के बहुआयामी सुरक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को पंगु बना दिया है। आतंकवाद को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्नत सतर्कता और निर्बाध आपसी समन्वय द्वारा आतंकवाद विरोधी हमलों

को और तेज करने का निर्देश दिया गया है। मोदी सरकार सुरक्षित और समृद्ध जम्मू-कश्मीर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिकारियों के अनुसार, राजभवन में आयोजित विकास समीक्षा बैठक में उपराज्यपाल मनोज और सीएम उमर अब्दुल्ला के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं जम्मू-कश्मीर सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विकास परियोजनाओं और कार्यों की समीक्षा बैठक लगभग दो घंटे चली। इसके बाद जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए अमित शाह की दूसरी समीक्षा बैठक हुई, जो लगभग ढाई घंटे तक चली।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी संगठन हुर्रियत को मंगलवार को झटका लगा। तीन बड़े संगठनों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से नाता तोड़ लिया है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी थी।

अमित शाह ने एक्स पर लिखा था, जम्मू-कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू-कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट जैसे तीन और संगठनों ने हुर्रियत से खुद को अलग कर लिया है। यह घाटी के लोगों में भारत के संविधान के प्रति विश्वास का एक प्रमुख प्रदर्शन है।

रक्षा संबंधों पर हुई बात

राजनाथ सिंह और यूएई के क्राउन प्रिंस के बीच मुलाकात

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात की, जो रक्षा मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे हैं। यह बैठक यहां साउथ ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय में हुई।

मंत्रालय के मुताबिक, दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि रक्षा सहयोग को व्यापार और अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति के अनुरूप बढ़ाने की आवश्यकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि यूएई के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, आने वाले वर्षों में, हम रक्षा सहयोग, सह-निर्माण, सह-विकास परियोजनाओं, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने को तत्पर हैं। भारत और यूएई दोनों ही क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध

हैं।रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस दौरान दोनों नेताओं ने संस्थागत तंत्र, सैन्य अभ्यासों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आदान-प्रदान आदि के माध्यम से वर्तमान रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने प्रशिक्षण आदान-प्रदान को रक्षा सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र माना और इसे दोनों देशों के रक्षा ढांचों को समझने और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने का माध्यम बताया।दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग पर बैठक में संतोष जताया गया और इसे एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योगों के बीच करीबी सहयोग को द्विपक्षीय साझेदारी का अभिन्न हिस्सा बताया। साथ ही इस मुलाकात में संयुक्त रक्षा निर्माण और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के अवसरों पर चर्चा की, एक-दूसरे की रक्षा प्रदर्शनियों और डिफेंस एक्सपो में सक्रिय भागीदारी की सराहना की और भारत-यूएई डिफेंस पार्टनरशिप फोरम का स्वागत किया। इस पार्टनरशिप फोरम से रणनीतिक संयुक्त उपक्रम और को-प्रोडक्शन परियोजनाएं संभव हो सकेंगी।इसके साथ ही मंगलवार को हुई इस बैठक में %मेक-इन-इंडिया% और %मेक-इन-एमिरेट्स% जैसी पहलों के बीच संभावित तालमेल पर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग पर पहला एमओयू वर्ष 2003 में और रक्षा उद्योग सहयोग पर एमओयू वर्ष 2017 में हस्ताक्षरित हुआ था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध सदियों पुराने और मजबूत मित्रता पर आधारित हैं।

म्यांमार में भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 3,645

यांगून। म्यांमार में 28 मार्च को आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,645 हो गई है, जबकि 5,017 लोग घायल हुए हैं और 148 लोग अब भी लापता हैं। यह जानकारी मंगलवार देर शाम राज्य प्रशासन परिषद की सूचना टीम ने दी।

देश के मौसम विज्ञान और जलवायु विभाग के अनुसार, भूकंप के बाद से अब तक 98 आफ्टरशॉक्स (भूकंप के झटके) दर्ज किए गए हैं, जिनकी तीव्रता 2.8 से लेकर 7.5 तक रही। इस भयानक आपदा के कारण सागाइंग, मांडले और मगवे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

यूएनडीपी के क्षेत्रीय प्रतिनिधि टिटॉन मित्रा ने मांडले से बताया कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से टूट चुकी है, अस्पतालों में मरीजों की भारी संख्या के कारण इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दवाइयों और स्वास्थ्य सामग्री

की भारी कमी है।संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओचीएचए) की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में 5 लाख से अधिक लोग बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो गए हैं। टिटॉन मित्रा ने बताया कि सागाइंग और मगवे जैसे क्षेत्रों में बाजार पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं, लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं बचा है और अब महंगाई तेजी से बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।

देश भर में आज से लागू हुआ नया वक्फ कानून, केंद्र ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना के बाद वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मंगलवार को आधिकारिक रूप से लागू हो गया। संसद में पारित होने के दो दिन बाद ही रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अधिनियम को मंजूरी दे दी थी।भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 8 अप्रैल, 2025 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तिथि निर्धारित करती है।मूल वक्फ अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन करने वाले इस कानून ने कई महत्वपूर्ण सुधार पेश किए हैं। इनमें वक्फ संस्थाओं से ट्रस्टों को अलग करना, संपत्ति प्रबंधन के लिए डिजिटल और तकनीकी उपकरणों की शुरुआत, बेहतर पारदर्शिता के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण, वक्फ संपत्ति को केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को समर्पित करने पर प्रतिबंध, समुदाय द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग की जाने वाली %वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता% संपत्तियों की सुरक्षा, पारिवारिक वक्फ में महिलाओं के अधिकारों को मान्यता, आदि शामिल है। यह विधेयक शुक्रवार तड़के 17 घंटे की मैराथन बहस के बाद राज्यसभा में पारित हो गया था। लोकसभा ने इस सप्ताह के शुरू में ही विधेयक को मंजूरी दे दी थी।

हम दलित, मुस्लिम-ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी हमारा साथ छोड़ गए : राहुल गांधी

अहमदाबाद । कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मंगलवार को राहुल गांधी का ओबीसी को लेकर दर्द उभर आया। राहुल ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और ओबीसी हमारा साथ छोड़ गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल ने यह भी कहा- हम मुस्लिमों की बात करते हैं, इसलिए हमें मुस्लिम परस्त कहा जाता है। हमें ऐसी बातों से डरना नहीं है। मुद्दे उठाते रहना है।ज्ञात रहे कि गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित हो रही है। इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। यह आजादी के बाद गुजरात में कांग्रेस का पहला कार्यक्रम था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुबह करीब 10.30 बजे अहमदाबाद पहुंचें। 9 अप्रैल को मुख्य अधिवेशन होगा, जिसमें देशभर से 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह कार्यक्रम साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा। यहां डोम बनाया गया है। इस अधिवेशन की थीम है, 'न्यायपथ-संकल्प, समर्पण, और संघर्ष।'पार्टी के मुताबिक यह अधिवेशन गुजरात में संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रोडमैप तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस साल महात्मा गांधी के बतौर कांग्रेस अध्यक्ष 100 साल पूरे हो रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भी है। दोनों ही महान विभूतियां गुजरात में पैदा हुई थीं, इसलिए कांग्रेस ये अधिवेशन गुजरात में कर रही है।

अल्लाह ने मुझे किसी वजह से जीवित रखा है : शेख हसीना

नई दिल्ली । बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि अल्लाह ने उन्हें किसी वजह से जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि वह दिन भी आएगा जब अवामी लीग के सदस्यों को निशाना बनाने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने यह टिप्पणी उस समय की जब वह सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी के नेताओं के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत कर रही थीं।पिछले अगस्त में शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। वह अपना देश छोड़ भारत आ गई थीं।हसीना ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद युनुस पर निशाना साधा और उन्हें %ऐसा व्यक्ति बताया जिसने कभी लोगों से प्यार नहीं किया।%बांग्लादेश की पूर्व पीएम ने कहा, उन्होंने ऊंची ब्याज दरों पर छोटी रकम उधार दी और उस पैसे का इस्तेमाल विदेश में शान-शौकत से रहने में किया। हम तब उसे समझ नहीं पाए, इसलिए हमने उसकी खूब मदद की। लेकिन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। उसने खुद के लिए अच्छा किया। फिर उसने सत्ता की ऐसी लालसा पैदा की जो आज बांग्लादेश को जला रही है।

77 वर्षीय नेता ने कहा कि विकास के मॉडल के रूप में देखा जाने वाला बांग्लादेश अब एक %आतंकवादी देश% बन गया है। उन्होंने कहा, हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरह से मारा जा रहा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

ट्रंप ने फिर अलापा गाजा पर कब्जा करने का राग, इजराइल ने किया समर्थन

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद फिर गाजा पर कब्जे का प्लान पेश किया है। उन्होंने कहा कि गाजा को शांत करने के लिए यही बेहतर होगा कि उस पर अमेरिका का कब्जा हो। इसके अलावा गाजा से फिलिस्तीनियों को हटा दिया जाए और अलग-अलग देशों में उन्हें बसा दिया जाए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से अपील करते हुए कहा कि यदि आप लोग इन फिलिस्तीनियों को बसा लें तो फिर गाजा में समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि गाजा को हम फ्रीडम जोन में तब्दील करना चाहते हैं। यदि फिलिस्तीनी अलग-अलग देशों में जाकर बस जाएं तो फिर गाजा में काम हो सकता है। उसे एक शांत इलाके के तौर पर विकसित किया जाएगा। ट्रंप के इस प्लान का नेतन्याहू ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम हमास के साथ एक नई डील पर भी विचार कर रहे हैं ताकि बंधकों को छुड़ाया जा सके, जो अब भी कैद में हैं।

ट्रंप ने सत्ता में आने के कुछ समय बाद ही गाजा को फिलिस्तीनियों से मुक्त कराने की बात कही थी और कहा था कि हम चाहेंगे कि वहां एक कॉलोनी विकसित की जाए। अमेरिका यह

काम अपने हाथ में ले सकता है। ट्रंप के इस प्लान की तीखी आलोचना हुई थी और कहा गया था कि यह तो नस्ल ही खत्म करने जैसी बात होगी, लेकिन अब ट्रंप ने एक बार फिर से वही बात दोहराई है। अब तक इस पर सऊदी अरब, तुर्की, मिस्त्र, कतर और कुवैत समेत किसी भी मुस्लिम देश की प्रतिक्रिया नहीं आई है।

नेतन्याहू से बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि आप जानते हैं कि गाजा में अमेरिकी सेना का नियंत्रण होना और उस पट्टी को विकसित करना अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि वहां मौतें हो रही हैं। कभी वहां हमास हत्याएं करता है तो कभी कुछ और समस्या खड़ी हो जाती है। उन्होंने मुस्लिम देशों से अपील करते हुए कहा कि यदि आप फिलिस्तीनियों को ले लें और उन्हें अलग-अलग देशों में बसा लें तो सही रहेगा। ऐसे बहुत से देश हैं, जो ऐसा कर सकते हैं। फिर आपके पास वास्तव में एक फ्रीडम जोन होगा। यह एक फ्री जोन होगा और यहां हर रोज लोग मारे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही एक और सीजफायर की उम्मीद कर रहे हैं। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि हमास की कैद में पड़े बंधकों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। हमें उनको रिहा कराना होगा।

सत्यवादी मंच संपादकीय

भारत का महा आर्थिक संकट, शेयर बाजार और बैंकों में हाहाकार

भारत में आर्थिक मंदी जिस तरह से सामने आ रही है। जिसमें अर्थतंत्र के सारे संस्थान डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर बाजार में पिछले 6 महीने से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट को थामने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ने लाखों करोड़ रुपया शेयर बाजार में डाला। वह रुपया भी मुनाफा वसूली में शेयर बाजार से बाहर निकल गया। रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में डिविडेंड के नाम पर काफी बड़ी राशि वसूल कर की है। जिसके कारण रिजर्व बैंक का आर्थिक संकट भी सामने दिख रहा है। रही सही कसर सरकारी बैंक पूरी कर रहे हैं। बैंकों द्वारा जो फाइनेंस किया गया है। उसकी वसूली नहीं हो पा रही है। बैंकों द्वारा पिछले वर्षों में खातेदारों से तरह-तरह के शुल्क लगाकर अनाप-शनाप वसूली की जा रही है। एनपीए खाते की रकम का समयोजन कर बैंकों का मुनाफा बैलेंस शीट में लाभ से एडजस्ट किया जा रहा है। पिछले वर्षों में शेयर बाजार में बैंकों द्वारा भारी निवेश किया गया है । जब तक शेयर बाजार मैं तेजी बनी हुई थी। तब तक बैंकों की बैलेंस शीट मुनाफा उगल रही थी। अब बैंकों की बैलेंस शीट घाटे की ओर आगे बढ़ रही हैं। जीवन बीमा निगम जैसी कंपनियां लड़खड़ा रही हैं । म्युचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थान भी शेयर बाजार की गिरावट के कारण आर्थिक हालत खराब होती चली जा रही है । भारत के करोडों परिवार कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है । उसके अनुसार 68 फीसदी कर्जदारों को ईएमआई चुकाने में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 45 अरब डॉलर का कर्ज फंसा हुआ है। 91 से 180 दिनों के भीतर लोन की किस्त जमा नहीं होने पर बैंक यह राशि एनपीए में डाल देते हैं। एनपीए 3.3 फ़ीसदी की रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है। 2023 में यह आंकड़ा मात्र 0.8 फीसदी था। भारत में लोन चुकाने के लिए अब लोग लोन ले रहे हैं। आर्थिक संकट के कारण लोगों को अपने बच्चों को स्कूलों से बाहर निकालना पड़ रहा है। बैंकों मे लोन डिफाल्टरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रिजर्व बैंक के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस के तहत बड़ी मात्रा में पर्सनल ऋण दिया गया है। इस ऋण की भी वसूली नहीं हो पा रही है। 10 में से 9 लोगों के पास औपचारिक और स्थाई नौकरी नहीं है। जिसके कारण वह लोन की किस्त नहीं चुका पा रहे हैं । समूह लोन जो दिया गया था, वह भी वसूल नहीं हो पा रहा है। माइक्रो फाइनेंस के लोन की किस्तें भी लोग नहीं चुका पा रहे हैं। लोगों के पास पर्याप्त आय नहीं है,उनकी मासिक खर्च लायक आमदनी नहीं हैं। माइक्रो फाइनेंस में रिजर्व बैंक ने न्यूनतम आय 3 लाख वार्षिक मानी है। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार पुर्नभुगतान के लिए 50 फ़ीसदी से ज्यादा वसूली नहीं की जा सकती है। माइक्रो फाइनेंस में परिवार के कई सदस्यों ने अलग-अलग लोन लिया हुआ है। संयुक्त परिवार की मासिक आय 20 से ?25000 के बीच आती है। माइक्रो फाइनेंस की किस्त ही प्रति परिवार को 15 से 20000 चुकाना पड़ रही है। जिसके कारण माइक्रो फाइनेंस में डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां मनमाना ब्याज वसूल कर रही है। जिसके कारण विवाद और आत्म हत्या जैसी घटनायें बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस शहरी क्षेत्र में ज्यादा बांटा गया है। आय की तुलना में कई गुना ज्यादा कर्ज होने से वित्तीय संस्थानों और बैंकों की हालत वसूली नहीं होने बड़ी खराब हो गई है। लोगों ने दिखावे के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लिए, अब वह कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं । बाजार में पैसा नहीं होने के कारण उत्पाद की बिक्री तेजी के साथ घटती चली जा रही है। जिसके कारण उद्योग और व्यापार भी संकट में आ गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टेरिफ़ बार शुरू किया है। उसने दुनिया के सभी देशों में आर्थिक मंदी का बिगुल बजा दिया है। इसमें सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ रहा है।

विश्व व्यापार संधि का अस्तित्व खतरे में

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में व्यापार युद्ध (टैरिफ वार) ने वैश्विक व्यापार संधि को लेकर, दुनिया के देशों में एक नई चिंता पैदा कर दी है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अंतरराष्ट्रीय संस्थान जिनके जिम्मे नियम और कानून का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग 166 देशों द्वारा वैश्विक व्यापार संधि में हस्ताक्षर किए हैं। उन देशों के कारोबार और आर्थिक स्थिति को लेकर संकट खड़ा हो गया है। हाल ही में अमेरिका ने टैरिफ को लेकर जो निर्णय लिए हैं। वह वैश्विक व्यापार संधि के खिलाफ हैं। उससे सारी दुनिया के देशों मे अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर तनाव बन गया है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टैरिफ युद्ध ने सभी देशों में वैश्विक व्यापार व्यवस्था को बुरी तरह से अस्थिर कर दिया है।

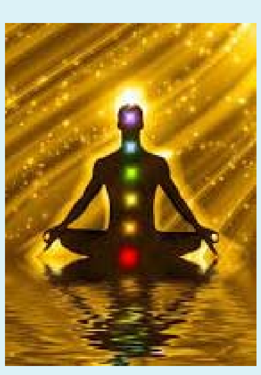

अमेरिका ने राष्ट्र हितों की दुहाई देकर चीन, भारत एवं अन्य देशों पर आयातित वस्तुओं पर भारी शुल्क लगा दिया है। वैश्विक व्यापार संधि के अनुसार उसको इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।अमेरिका एक तरफा निर्णय ले रहा है। दूसरी ओर चीन ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रतिशोधात्मक नीति का प्रभाव सारी दुनिया के देशों के साथ-साथ अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। इस टकराव के कारण दुनिया के 166 देशों में व्यापारिक स्थिरता को लेकर बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। यह स्थिति तब और भी चिंताजनक हो जाती है। जब वैश्विक व्यापार संधि को नियंत्रित करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इस विवाद में निषप्रभावी दिखाई पड रही हैं। दुनिया के सभी देशों के बीच वैश्विक व्यापार संधि का मूल उद्देश्य सभी देशों के बीच व्यापार विवादों का समाधान करना और वैश्विक व्यापार को सभी देशों के लिए मुक्त व्यापार के लिये अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सभी देशों के लिये निष्पक्ष एवं स्थिर नीति को बनाना और उनका पालन करने की जिम्मेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ युद्ध की शुरुआत की है। इसमें दो बड़ी वैश्विक शक्तियां अमेरिका और चीन वैश्विक व्यापार संधि के नियमों की अनदेखी करते हुए एक दूसरे के ऊपर मनमाने तरीके से टैरिफ लगाने की होड़ में लग गए हैं।

आरएसएस मुख्यालय में मोदी-क्या यह संघम शरणं गच्छामि है?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हाल में नागपुर-स्थित आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉ के।बी। हेडगेवार और द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। इस यात्रा का खूब प्रचार हुआ और इसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का कयास है कि चूँकि अगले सितम्बर में मोदी 75 साल के हो जाएंगे और अपनी पार्टी के नियमों के अनुसार उन्हें सक्रिय राजनीति से सन्यास लेना होगा, इसलिए यह उनकी फेयरवेल यात्रा थी!

इस बीच कई घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि पिता (आरएसएस) और बेटे (भाजपा) के रिश्तों में कुछ खटास आ गयी है। सन 2024 के आमचुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष जे।पी। नड्डा ने कहा था कि भाजपा अब अपने पैरों पर खड़ी हो गयी है और उसे आरएसएस के समर्थन की ज़रुरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके पहले तक भाजपा इतनी मज़बूत नहीं थी इसलिए उसे वोट हासिल करने के लिए आरएसएस की मदद की दरकार रहती थी।एक दूसरा मसला है मोदी का आसमान छूता अहंकार। उन्होंने कहा कि वे नॉन-बायोलॉजिकल हैं और ईश्वर ने उन्हें इस धरती पर अपना दूत बनाकर भेजा है। संघ के मुखिया मोहन भागवत को लगा कि मोदी का अहं बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की कि कुछ लोग खुद को देवता और फिर भगवान मानने लगते हैं।लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों में कमी आई। ऐसा माना जाने लगा कि आरएसएस ने चुनाव में पूरा जोर नहीं लगाया और इसलिए भाजपा को नुकसान हुआ। मगर फिर महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में आरएसएस, भाजपा के समर्थन में कूद पड़ा। जहाँ तक आरएसएस का प्रश्न है, सिवाय 1984 के चुनाव के, जब संघ को लगने लगा था कि खालिस्तान आन्दोलन भारत की एकता के लिए खतरा है, उसने भाजपा का साथ दिया है और उसे वोट दिलवाने में मदद की है। आरएसएस, संघ परिवार का मुखिया और मुख्य योजनाकार है। उसकी राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा यह सुनिश्चित करती है कि संघ के अनुषांगिक संगठन अपना-अपना काम करते हुए भी आरएसएस की विचारधारा का प्रचार करें - अतीत (मनुस्मृति) का महिमामंडन करें, मुसलमानों और ईसाईयों के खिलाफ नफरत फैलाएं और लोगों को बताएं कि ईसाई धर्म और इस्लाम विदेशी हैं। चुनावों के दौरान संघ और उससे जुड़े संगठन भाजपा की जीत के लिए पूरा जोर लगाते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हिन्दू महासभा के श्यामाप्रसाद मुख़र्जी ने की थी। मुख़र्जी के देहांत के बाद संघ ने धीरे-धीरे जनसंघ पर कब्ज़ा जमा लिया। इससे आरएसएस को अपने अधीन काम करने वाला एक विशुद्ध राजनैतिक संगठन हासिल हो गया। आरएसएस, भाजपा और संघ के अन्य बाल-बच्चों के बीच एकदम स्पष्ट श्रम विभाजन है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण था 1980 के दशक में विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा शुरू किया गया राममंदिर आन्दोलन। भाजपा ने इस आन्दोलन को अपने हाथों में ले लिया और उसके ज़रिये जमकर वोट कबाड़े। आरएसएस लगातार प्राचीन भारत का महिमामंडन करता है और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमज़ोर वर्गों जैसे दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के बारे में गलत धारणाएं फैलाता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी शाखाओं का विशाल जाल और लोगों से जुड़ने की उसकी कई कार्यविधियाँ।यद्यपि भारत का सामंती और औपनिवेशिक समाज अब प्रजातान्त्रिक बन चुका है मगर आरएसएस अब भी अपनी शाखाओं के ज़रिये राजे-रजवाड़ों के दौर में व्याप्त जातिगत और लैंगिक ऊंचनीच और सामंती मूल्यों को बढ़ावा देता है। उससे जुड़े एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती, राष्ट्रसेविका समिति आदि भी यही काम करते हैं।समाज के विभिन्न तबकों और राजनैतिक ढांचे में घुसपैठ करने का काम आरएसएस बहुत लम्बे समय से कर रहा है। मगर पहले राज्यों और अब केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने से इस प्रक्रिया में जबरदस्त तेजी आई है। अब संघ अपनी विचारधारा को और फैलाने के लिए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के समूह गठित कर रहा है। मैं मुंबई के जिस इलाके में रहता हूँ, वहां संघ ने हाल में एक पिकनिक का आयोजन किया। एक मुस्लिम महिला उसमें भाग लेना चाहती थी मगर उसे सीधे-सीधे कह दिया गया कि पिकनिक के दौरान जो बातें की जाएंगी उससे वो असहज महसूस करेगी। सुबह-सुबह हाथों में लाठियां लिए जाती महिलाओं को देखकर आप यह समझ सकते हैं कि वे राष्ट्र सेविका समिति की शाखा में जा रहीं हैं।पिछले एक दशक के भाजपा शासन में आरएसएस के अपने हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडा के कई लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। राममंदिर बन चुका है, अनुच्छेद 370 हटाया जा चुका है, मुंहजबानी तलाक गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। वक्फ के मामले में संसद में बहस चल रही है।यह साफ़ है कि आरएसएस और भाजपा के बीच कोई विवाद या असहमति नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि दोनों के बीच हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति के मामले में कुछ मतभेद हों।मोदी ने हेडगेवार और गोलवलकर के तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने देश को सही राह दिखाई। वह राह क्या है? पहली तो यह कि आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के मूल्यों को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाले भारतीय राष्ट्रवादी आन्दोलन से सुरक्षित दूरी बनाई रखी जाए। दूसरे बिना स्वीकार करे गोलवलकर के इस सिद्धांत का पालन किया जाए कि मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट हिन्दू राष्ट्र के दुश्मन हैं। इस साल (2025) की ईद-उल-फ़ित्र इसका उदाहरण हैं। एक राज्य में उसे सार्वजनिक की बजाय ऐच्छिक छुट्टी घोषित कर दिया गया। सड़क पर नमाज़ अदा करने का विरोध किया जा रहा है और पुलिस नमाजियों के खिलाफ बलप्रयोग कर रही है।

जहाँ तक ईसाईयों का सवाल है, ओड़िशा में उनके शवों को दफनाना मुश्किल बना दिया गया है। बालासोर जिले में सरना माझी नामक एक आदिवासी संस्था यह बेबुनियाद दावा कर रही है कि संविधान के अनुच्छेद 13(3)ए के अंतर्गत आदिवासी ईसाईयों को उनके गांवों में अपने लोगों का शव दफ़न करने का हक़ नहीं है। (बालासोर की यात्रा पर गयी एक तथ्यान्वेषण समिति की रपट)।मोदी बार-बार कह रहे हैं कि भारत विकसित हो रहा है। शायद वह आरएसएस की विचारधारा के परिप्रेक्ष्य से विकसित हो रहा होगा। मगर आनंद, धार्मिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रजातंत्र और भूख से सम्बंधित मानकों में तो उसी स्थिति गिरती ही जा रही है। शायद विकास से मोदी का आशय यह है कि कुछ चुनिन्दा घराने और रईस होते जायें और वे या तो यहाँ के कानूनों का मखौल बनाते रहें या बैंकों से अरबों का कर्ज लेकर विदेश भाग जाएँ। जाहिर है कि कथनी और करनी में भारी भेद है।मोदी की नागपुर यात्रा के राजनैतिक निहितार्थ हैं। उन्होंने वहां जो किया और कहा वह एक राजनैतिक प्रहसन है जिसका उद्देश्य वोट हासिल करना है।

टैरिफ युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं होगा अधिक प्रभाव

दिनांक 2 अप्रेल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा, विभिन्न देशों से अमेरिका में होने वाले आयातित उत्पादों पर की गई टैरिफ सम्बंधी घोषणा के साथ ही अंततः अमेरिका द्वारा पूरे विश्व में टैरिफ के माध्यम से व्यापार युद्ध छेड़ दिया गया है। अभी, अमेरिका ने विभिन्न देशों से अमेरिका में होने वाले आयात पर विभिन्न दरों पर टैरिफ लगाया है। अब इनमें से कई देश अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहे हैं, जैसे चीन ने अमेरिका से चीन में आयात होने वाले उत्पादों पर दिनांक 10 अप्रैल 2025 से 34 प्रतिशत की दर से टैरिफ लगाने की घोषणा की है। टैरिफ के माध्यम से छेड़े गए व्यापार युद्ध का भारत पर कोई बहुत अधिक विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना कम ही है। दरअसल, अमेरिका ने विभिन्न देशों से आयातित उत्पादों पर अलग अलग दर से टैरिफ लगाने की घोषणा की है और साथ ही कुछ उत्पादों के आयात पर फिलहाल टैरिफ की नई दरें लागू नहीं की गई हैं। टैरिफ की यह दरें 9 अप्रैल 2025 से लागू होंगी।

विभिन्न देशों से अमेरिका में आयात होने वाले उत्पादों पर 10 प्रतिशत की दर से न्यूनतम टैरिफ लगाया गया है। साथ ही, कुछ अन्य देशों यथा चीन से आयातित उत्पादों पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है। इसी प्रकार, वियतनाम से आयातित उत्पादों पर 46 प्रतिशत, ताईवान पर 32 प्रतिशत, थाईलैंड पर 36 प्रतिशत, भारत पर 26 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया पर 25 प्रतिशत, इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत, स्विट्जरलैंड पर 31 प्रतिशत, मलेशिया पर 24 प्रतिशत, कम्बोडिया पर 49 प्रतिशत, दक्षिणी अफ्रीका पर 30 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत, पाकिस्तान पर 29 प्रतिशत, श्रीलंका पर 44 प्रतिशत और इसी प्रकार अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर भी अलग अलग दरों से टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है। कुछ उत्पादों जैसे, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो, ताम्बा, फार्मा उत्पाद, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, बुलीयन एवं अन्य महत्वपूर्ण मिनरल्स को अमेरिका में आयात पर टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है।

अमेरिका का मानना है कि वैश्विक स्तर पर अन्य देश अमेरिका में उत्पादित वस्तुओं के आयात पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाते हैं, जबकि अमेरिका में इन देशों से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर अमेरिका द्वारा बहुत कम दर पर टैरिफ लगाया जाता है अथवा बिलकुल नहीं लगाया जाता है। जिससे, अमेरिका से इन देशों को निर्यात कम हो रहे हैं एवं इन देशों से अमेरिका में आयात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार, अमेरिका का व्यापार घाटा असहनीय स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ साथ, अमेरिका में विनिर्माण इकाईयां बंद होकर अन्य देशों में स्थापित हो गई हैं और इससे अमेरिका में रोजगार के नए अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे हैं। अब ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका को पुनः विनिर्माण इकाईयों का हब बनाने के उद्देश्य से अमेरिका को पुनः महान बनाने का आह्वान किया है और इसी संदर्भ में विभिन्न देशों से आयातित उत्पादों पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाने का निर्णय लिया गया है ताकि अमेरिका में आयातित उत्पाद महंगे हों और अमेरिकी नागरिक अमेरिका में ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने की ओर प्रेरित हों।

वर्तमान में बढ़े हुए टैरिफ का बोझ अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में महंगे उत्पाद खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की अमेरिका में स्थापना हो एवं इन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को महंगे उत्पाद खरीदने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। इससे अमेरिका में एक बार पुनः मुद्रा स्फीति की समस्या उत्पन्न हो सकती है एवं ब्याज दरों के कम होने के चक्र में भी देरी होगी, बहुत सम्भव है कि मुद्रा स्फीति को कम करने की दृष्टि से एक बार पुनः कहीं ब्याज दरों के बढ़ने का चक्र प्रारम्भ न हो जाए। लम्बे समय में जब अमेरिका में विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो जाएगी एवं इन इकाईयों में उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा तब जाकर कहीं मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाया जा सकेगा। विभिन्न देशों से आयातित उत्पादों पर टैरिफ सम्बंधी घोषणा के साथ ही, डॉलर पर दबाव पड़ना शुरू भी हो चुका है एवं अमेरिकी डॉलर इंडेक्स घटकर 102 के स्तर पर नीचे आ गया है जो कुछ समय पूर्व तक लगभग 106 के स्तर पर आ गया था। इसी प्रकार अमेरिका में सरकारी प्रतिभूतियों की 10 वर्ष की बांड यील्ड पर भी दबाव दिखाई दे रही है और यह घटकर 4.08 के स्तर पर नीचे आ गई है, यह कुछ समय पूर्व तक 4.70 के स्तर से भी ऊपर निकल गई थी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़नी प्रारम्भ हो गई है एवं यह पिछले चार माह के उच्चतम स्तर, लगभग 85 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर, पर आ गई है। ट्रम्प प्रशासन के टैरिफ सम्बंधी लिए गए निर्णयों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर लम्बी अवधि में तो हो सकता है परंतु छोटी अवधि में तो निश्चित ही यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को विपरीत रूप से प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहा है। अमेरिकी पूंजी बाजार (शेयर बाजार) केवल दो दिनों में ही लगभग 10 प्रतिशत तक नीचे गिर गया है और अमेरिकी निवेशकों को लगभग 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुक्सान हुआ है। इतनी भारी गिरावट तो वर्ष 2020 में कोविड महामारी के दौरान ही देखने को मिली थी। यदि यही स्थिति बनी रही तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था कहीं मंदी की चपेट में न आ जाय। यदि ऐसा होता है तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी विपरीत रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। अतः ट्रम्प प्रशासन का टैरिफ सम्बंधी उक्त निर्णय अति जोखिम भरा ही कहा जाएगा।

जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी कुछ तो विपरीत असर होगा ही। इस संदर्भ में किए गए विश्लेषण से यह तथ्य उभरकर सामने आ रहा है कि बहुत सम्भव है कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए 26 प्रतिशत के टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक विपरीत प्रभाव नहीं हो। क्योंकि, एक तो भारत से अमेरिका को निर्यात बहुत अधिक नहीं है। यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र लगभग 3-4 प्रतिशत ही है। वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर नहीं है एवं यह विभिन्न उत्पादों की आंतिरक मांग पर अधिक निर्भर है। भारत से सकल घरेलू उत्पाद का केवल लगभग 16 प्रतिशत (वस्तुएं एवं सेवा क्षेत्र मिलाकर) ही निर्यात किया जाता है। दूसरे, भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने कुछ उत्पादों को उक्त टैरिफ व्यवस्था से फिलहाल मुक्त रखा गया है, जैसे फार्मा उत्पाद, सेमीकंडक्टर, स्टील, अल्यूमिनियम, ऑटो, ताम्बा, बुलीयन, एनर्जी आदि। संभवत- इन उत्पादों के भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर कुछ भी असर नहीं होने जा रहा है। तीसरे, भारतीय कम्पनियों (26 प्रतिशत टैरिफ) को रेडीमेड गर्मेंट्स के अमेरिका को निर्यात में पड़ौसी देशों, यथा, बांग्लादेश (37 प्रतिशत टैरिफ), पाकिस्तान (29 प्रतिशत टैरिफ), श्रीलंका (44 प्रतिशत टैरिफ), वियतनाम (46 प्रतिशत टैरिफ), चीन (34 प्रतिशत टैरिफ), इंडोनेशिया (32 प्रतिशत टैरिफ), आदि के साथ अत्यधिक स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। परंतु, उक्त समस्त देशों से अमेरिका को होने वाले रेडीमेड गार्मेंट्स के निर्यात पर भारत की तुलना में अधिक टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की गई है। अत- इन देशों से रेडीमेड गार्मेंट्स के अमेरिका को निर्यात भारत की तुलना में महंगे हो जाएंगे, इससे रेडीमेड गार्मेंट्स के क्षेत्र में भारत के लिए लाभ की स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कृषि उत्पादों के निर्यात भी भारत से अमेरिका को बढ़ सकते हैं। यदि किन्ही क्षेत्रों में भारत को नुक्सान होता हुआ दिखाई भी देता है तो भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ बहुत अच्छे राजनैतिक संबंधो के चलते भारत को अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी, अमेरिका सहित भारत के यूरोपीयन देशों, ब्रिटेन एवं खाड़ी के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को सम्पन्न करने हेतु वार्ताएं लगभग अंतिम दौर में पहुंच गईं हैं, इसका लाभ भी भारत को होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शीघ्र ही मोनेटरी पॉलिसी के माध्यम से रेपो दरों में परिवर्तन की घोषणा की जाने वाली है। भारत में चूंकि मुद्रा स्फीति की दर लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है

ट्रम्प की सनकी नीतियां बदल देंगी वैश्विक परिदृश्य

डोनाल्ड ट्रम्प एक सनकी मिजाज़ इंसान हैं ये हमेशा कहा गया है। जब से उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से डोनाल्ड ट्रम्प खुद को दुनिया का स्वघोषित बॉस सिद्ध करना चाहते हैं। हालांकि टैरिफ टैरिफ चिल्लाते हुए ट्रम्प खुद ही एक मज़ाक बनकर रह गए हैं। भारत, यूरोपीय देशों, चाइना आदि के साथ टैरिफ, टैरिफ खेल रहे हैं। दर-असल डोनाल्ड ट्रम्प को लगता है अगर पूरी दुनिया पर टैरिफ रेट बढ़ा देंगे तो पूरी दुनिया उनके कदमों में गिरेगी ! वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्लादिमीर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बेइज्जत करना, या निरंतर भारत गणराज्य के खिलाफ़ बोलना उन्हें अमेरिका में बसे भारतीयों के बीच निंदा का पात्र बनना पड़ रहा है, चूंकि अमेरिका में भारतीयों की ताकत क्या है किसी से छुपा नहीं है। ग़ैर वीज़ा के रह रहे लोगों को जानवरों की तरह उन्हें मुल्क से निकालना डोनाल्ड ट्रम्प के इस फैसले ने उन्हें एक सनकी असंवेदनशील इंसान घोषित कर दिया है।

कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ को लेकर इतना झल्लाए हुए हैं कि लगता है उनके मुँह से टैरिफ के अलावा दूसरा शब्द मुश्किल से ही निकलता होगा। ग़ज़ब तो तब हो गया जब यूरोपीय देशों एवं चाइना, कनाडा ने भी अमेरिका पर टैरिफ रेट बढाकर ट्रम्प को मुँहतोड़ जवाब दिया है। कोई भी संप्रभुतावादी मुल्क हो उसको यही करना चाहिए। हालांकि दुःख होता है जब भारत सरकार टैरिफ को लेकर ट्रम्प की इस नीति का विरोध नहीं किया, भारत हमेशा से ही गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थक रहा है, अमेरिका भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन भारत की संप्रभुता का सम्मान करे भारत जैसे मुल्क को ट्रम्प रोज टैरिफ की धमकी देते रहते हैं। अब तक भारत सरकार की चुप्पी खल रही है, जब सभी मुल्क ट्रम्प के सामने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते दिख रहे हैं तो हम चुप क्यों हैं ?

डोनाल्ड ट्रंप आजकल अपने मुल्क में ही मज़ाक के पात्र बने हुए हैं। इन दिनों अमेरिका में अपने नागरिकों का कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में अमेरिकी नागरिकों ने शनिवार को अमेरिका के अलग-अलग शहरों में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ रैलियां निकाली। बताया जा रहा है कि इन रैलियों का मकसद टैरिफ, कर्मचारियों की छंटनी, अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और मानवाधिकार समेत कई मुद्दों पर अपना विरोध जताने का है। ये प्रदर्शनकारी ट्रंप सरकार के कई कार्यकारी आदेशों के खिलाफ भी सड़कों पर उतरे हैं। ट्रंप की नीतियों का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कर्मचारियों में कटौती से लेकर व्यापार शुल्क और नागरिक स्वतंत्रता के हनन के मुद्दे वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, फ्लोरिडा, कोलोराडो और लॉस एंजिल्स सहित अन्य शहरों में रैली निकाली।

न्यूयॉर्क की चित्रकार शाइना केसनर ने इस प्रदर्शन को लेकर कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूं। इस सरकार की नीतिया सही नहीं लग रही हैं। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारे पास लगभग 100 लोग हैं जो न्यू हैम्पशायर से बस और वैन द्वारा इस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमें दुनिया भर में अपने सहयोगियों को खोना पड़ रहा है, पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ़ हो गई है हम ये नहीं चाहते और यहां घर पर लोगों के लिए तबाही का कारण बन रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित हूं। आज मैं यहां हूं क्योंकि यह हमारा महासागर और हमारा नमक है। जहां तक ??विश्व वाणिज्य और विश्व विनिमय का सवाल है। हमारे पास एक-दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है। पहले मैं, पहले मेरा देश, पहले मेरा उत्पाद का यह लालच दुनिया और मानवता के लिए अस्थिर है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप और मस्क को अमेरिका के लिए खतरा बताया और कहा कि दोनों मिलकर देश को नष्ट करने में लगे हुए हैं। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, मैं लगभग दो साल से कोलकाता में रह रहा हूं। यह वह शहर है, जहां देवी मां काली, एक महान और शक्तिशाली शक्ति अभी भी निवास करती हैं। वह शक्ति पूरे भारत और दुनिया में निवास करती हैं। वाशिंगटन स्मारक पर हम सभी लोग आज कह रहे हैं कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प इतिहास में अपराधियों के रूप में जाने जाएंगे। इन लोगों को सत्ता में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालते ही इस बात का भी ऐलान किया था कि अब अमेरिका में सिर्फ दो जेंडर यानी महिला और पुरुष ही रहेंगे। किसी भी जगह पर तीसरे जेंडर के लोगों को जगह नहीं मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान तीसरे जेंडर का मामला भी उठाया जा रहा है। ट्रंप सरकार की नीतियों के खिलाफ शनिवार को अमेरिका भर में 1000 से ज्यादा प्रदर्शन किए गए। इन प्रदर्शन का नाम हैंड्स ऑफ रखा गया था। इनमें नागरिक अधिकार संगठनों, श्रमिक संघों, पूर्व सैनिकों और चुनाव कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले ही भारत समेत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने भारत पर भी 26 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। भारत के अलावा और जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया उनमें चीन, मलेशिया, कनाडा, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद से अक्सर विरोध-प्रदर्शन होते रहे हैं लेकिन हैंड्स ऑफ! प्रोटेस्ट महिला मार्च 2017 और ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन 2020 के बाद सबसे बड़ा जनांदोलन माना जा रहा है। लेकिन कई प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि शनिवार की ये लहर सिर्फ शुरुआत है। ट्रम्प सोच रहे थे टैरिफ बढ़ाकर पूरी दुनिया को झुका लेंगे लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प अपने देश के लोगों के द्वारा ही नकारे जा रहे हैं।

सूरत शहर के पांडेसरा स्थित मनपा के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

हजार से अधिक हानिकारक कोल्ड ड्रिंक जब्त

सूरत। शहर में गरमी बढ़ते ही ठंडे पीणे की मांग बढ़ रही है। वहीं कई लोग ईस का फायदा उठाकर बाजार में नकली ठंडे पेय आद बेच रहे है। इसी बीच सूरत नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने पांडेसरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए हानिकारक कोल्ड ड्रिंक्स और अखाद्य खाद्य पदार्थों का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 1000 से अधिक पेप्सी के डिब्बे, 80 किलो अखाद्य खाद्य सामग्री और 7 लीटर फलों का जूस जब्त कर नष्ट कर दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पांडेसरा क्षेत्र में कुछ थोक विक्रेता बिना लाइसेंस और प्रमाणीकरण के कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहे थे, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में पेप्सी, फ्रूटी और अन्य ठंडे पेय बरामद किए।

स्वास्थ्य अधिकारी प्रशांत पाटिल ने जानकारी दी कि हाल ही में पांडेसरा, उधना और डिंडोली क्षेत्रों में डायरिया, उल्टी और बुखार जैसे मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। इन बीमारियों का कारण संदिग्ध और मिलावटी पेय पदार्थ भी हो सकते हैं, इसलिए यह कार्रवाई जनहित में की गई है।नगर निगम ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल मान्यता प्राप्त ब्रांड और प्रमाणित कंपनियों के कोल्ड ड्रिंक्स का ही उपयोग करें। साथ ही यदि किसी दुकान या विक्रेता के पास संदिग्ध या अनधिकृत खाद्य सामग्री बिकती दिखाई दे, तो इसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दी जाए।यह कार्रवाई सूरत नगर निगम की स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, और साथ ही दुकानदारों के लिए भी एक सख्त संदेश है कि स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पानीपूरी फैक्ट्री पर मनपा का छापा

पांडेसरा इलाके में पानीपूरी बनाने वाली फैक्ट्री पर

सूरत। सूरत शहर के पांडेसरा क्षेत्र में सोमवार को भी मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। गर्मी के दौरान लोग अधिक ठंडे खाद्य पदार्थ तथा बाहर का खाना खाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया और उल्टी के बढ़ते मामलों के चलते गंदगी में बनाई जा रही पानी पूरी को नष्ट किया गया।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पांडेसरा गोवालक क्षेत्र में स्थित पानीपुरी फैक्ट्री पर छापा मारकर जांच की। जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जिस जगह पानीपुरी बनाई गई थी वह बहुत गंदी थी। पता चला कि पानी पूरी गंदगी से घिरे माहौल में बनाई जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग ने मौके से बड़ी मात्रा में तैयार पूड़ियां जब्त कर नष्ट कर दीं।जुर्माने की कार्यवाही भी की गई।सूरत शहर के स्वास्थ्य विभाग ने मानसून पूर्व सावधानियों के तहत पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों का विशेष निरीक्षण शुरू किया है। खाद्य विभाग ने शहर के विभिन्न जोनों में पानीपुरी व खाद्य सामग्री बेचने वाली 45 दुकानों की जांच की। इस अभियान के दौरान 39 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया तथा 368 किलोग्राम माल नष्ट कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 25,075 रुपये मूल्य का माल नष्ट कर 26,450 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई सेंट्रल जोन और उधना जोन–ए में की गई।

सीवेज ओवरफ्लो बना लोगों की परेशानी का सबब

पूना रोड स्थित बॉम्बे मार्केट के पास सड़कों पर फैला गंदा पानी

सूरत। सूरत के वराछा जोन में बॉम्बे मार्केट से पूना रोड की ओर जाने वाली सड़क पर पिछले कई दिनों से सीवर लाइन जाम होने के कारण सीवेज ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। संस्कार धाम सोसायटी के पास गंदे पानी का सड़कों पर बहना अब स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है।भीषण गर्मी के बीच सीवेज का यह पानी सड़कों पर फैलकर दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है। पीक ट्रैफिक समय में गंदे पानी के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवेज का पानी उनके घरों के पास तक जमा हो जाता है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है।स्थानीय नागरिकों ने कई बार नगर पालिका से शिकायत करने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीवर लाइन की सफाई और मरम्मत की जाए, ताकि महामारी फैलने से पहले स्थिति पर काबू पाया जा सके।यदि समय रहते नगर निगम ने कार्रवाई नहीं की, तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। जनता अब अधिकारियों की ओर कार्रवाई की उम्मीद से देख रही है।

शहर में हीटवेव : पारा 40.4 डिग्री तक पहुंचा

सूरत। शहर में गरमी में बढ़ोत्तरी हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तर दिशा से आ रही गर्म, शुष्क हवाओं के कारण अधिकांश जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। सोमवार को सूरत में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा और पारा 40.4 डिग्री तक पहुंच गया। दोपहर के समय सड़के सूनसान दिखायी दिए। गर्मी के चलते लोगों ने दोपहर के समय बाहर जाना टाला। दक्षिण गुजरात में 9 से 10 अप्रैल तक असहनीय गर्मी रहेगी। जबकि कच्छ, उत्तर गुजरात, सुरेन्द्र नगर, राजकोट समेत कई जिलों में लू को लेकर अलग–अलग अलर्ट जारी किए गए हैं। इसलिए अगले 3 दिनों तक पूरा गुजरात भीषण गर्मी से तपेगा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को सूरत शहर में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौजूदा गर्मी के मौसम में सबसे अधिक तापमान मार्च में 41.8 डिग्री दर्ज किया गया था। सूरत अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी से प्रभावित रहेगा। संभावना जताई जा रही है कि पारा फिर 41 डिग्री को पार कर जाएगा।

बापू के पदचिन्हों पर ऐतिहासिक पदयात्रा, दांडी से सूरत के भीमराड तक

सूरत। महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह को लेकर दांडी कूच यात्रा 1930 में आरंभ की थी। ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की स्मृति में दांडी से सूरत के भीमराड गांव तक एक ऐतिहासिक पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा 6 अप्रैल को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। यात्रा का समापन 9 अप्रैल को सूरत के भीमराड गांव में होगा, जहां एक विराट जनसभा का आयोजन भी प्रस्तावित है।

दांडी,जो नवसारी जिले में अरब सागर के तट पर स्थित है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का प्रतीक स्थल है।9 अप्रैल 1930 को गांधीजी ने इसी तट पर नमक उठाकर ब्रिटिश शासन के कानूनों के खिलाफ जनआंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन ने देश की स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी।इस पदयात्रा का उद्देश्य गांधीजी के विचारों को जन–जन तक पहुंचाना और सत्याग्रह के मूल संदेशों को पुनः जीवंत करना है। सूरत के भीमराड गांव में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सत्याग्रह की 95वीं वर्षगांठ पर इस ऐतिहासिक यात्रा को फिर से दोहराया जाए। यात्रा की शुरुआत में बड़ी संख्या में जनसमूह शामिल हुआ।

आज रोज तारीख 07 अप्रेल 2025 शाम 04 बजे नुरू भाई चाइनीज ने UCC (UNIFORM CIVIL CODE) के विरोध में सूरत शहर के कलेक्टर श्री को आवेदन देके अपना विरोध दर्ज कराया जिस में तमाम अलग–अलग समाज के आगेवन मौजूद थे सूरत वासियों ने उनके साथ खंदे से खंदा मिले के विरोध दर्ज किया

बढ़ती गरमी को देखते हुए स्मीमेर अस्पताल में मरीजों के लिए तैयारी

सूरत। गुजरात में गरमी बढ़ते ही हिटवेव की संभावना बढ़ गई है। शहर के ईलाज के लिए जिले सीब लोग यहां आते है। इसी को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए स्मीमेर अस्पताल में कलर की व्यवस्था की है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही राज्य में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। कुछ शहरों में पारा 38 डिग्री को पार करने लगा है और गर्मी बढ़ने लगी है,चिलचिलाती धुप और गर्मी से अब लोग गर्मी बेहाल होने लगे हैं। इतना ही नहीं, राज्य के कुछ शहरों में हीटवेव का भी अनुमान जताया गया है। इन परिस्थितियों में नागरिकों के लिए

गर्मी और धुप से बचना बहुत जरूरी हो गया है। गर्मी के वजह डिहाइड्रेशन के मामले भी बढ़ रहे हैं। इन पूरी परिस्थितियों और हीटवेव की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्मीमेर अस्पताल प्रसाशन ने मरीजों और उनके साथ रहने वाले परिजनों को कोई परेशानी न हो और गर्मी बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ स्मीमेर अस्पताल में प्रतिदिन हजारों मरीज विभिन्न ओपीडी में इलाज के लिए आते हैं।

हज यात्रियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

सूरत। हज प्रशिक्षण शिविर (लगातार 29वां वर्ष) ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा 2025 में हज पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन रविवार दिनांक 06/04/2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ख्वाजा गरीब नवाज ओपीडी सेंटर, गोपीपुरा में किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं के लिए चाय, पानी व नाश्ते की व्यवस्था की गई थी।

इसके अलावा हज के बारे में तकनीकी जानकारी भी दी गई जैसे हज सुविधा आवेदन, एसबीआई फॉरेक्स कार्ड के फायदे और नुकसान, सऊदी रियाल कहां से प्राप्त करें आदि। मुख्य अतिथि मुनाफ पटेल, शब्बीर दादा, जाविद कड़ीवाला, सलीम भाई मेमन (सभी एफटी गुजरात स्टेट हज कमेटी सूरत), गुल अहमद (संपादक हिंदुस्तान की एकता न्यूज) थे।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष आसिफ भाई चिदिमार, उपाध्यक्ष सब्बीर भाई दादा, सचिव फैयाज भाई चिदिमार, हसन चिदिमार, जलील भाई, कादर भाई, इरफान भाई, इरशाद भाई, रफीक भाई, बकुल पटेल, मुस्ताक भाई, उवेश नवीवाला, अब्दुल वहाब, अब्दुल सत्तार और कई अन्य कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंबाजी में आदिशक्ति राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का प्रारंभ कराया

अहमदाबाद । मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आद्यशक्ति धाम अंबाजी में आयोजित आदिशक्ति राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का मंगलवार को प्रारंभ कराते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी सक्रिय प्रतियोगिता का आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में नए युग के नए भारत की तसवीर है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन खेल–कूद तथा पर्यटन को प्रोत्साहन देते हुए राज्य सरकार के खेल–कूद, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधि विभाग तथा पर्यटन विभाग के सहयोग से किया गया है। इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों की 550 से अधिक युवा नारी तीरंदाज तीन कैटेगरी की प्रतियोगिताओं में सहभागी हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता में विजेताओं को कुल 41.50 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तीर–कमान की कला को खेल–कौशल के रूप में आत्मसात करने वाली देशभर की बेटियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा व मार्गदर्शन में देश में नारीशक्ति के कौशल को निखारने के अवसर खेल–कूद क्षेत्र के अतिरिक्त उद्यमिता, स्टार्टअप, इनोवेशन क्षेत्रों में भी मिले हैं। भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि गुजरात ने भी खेल महाकुंभ का आयोजन प्रधानमंत्री के दिशा–दर्शन में करके राज्य की महिला खिलाड़ियों सहित खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलने–निखरने का अवसर दिया है। इस संदर्भ में उन्होंने देश को गौरव दिलाने वाली गुजरात की महिला खेल प्रतिभाओं सरिता गायकवाड, पैरा एथलीट भाविना पटेल तथा आर्चरी खेल में राज्य को देश में गौरव दिलाने वाली भार्गवी भगोरा, मैत्री पढियार का विशेष उल्लेख किया। भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार द्वारा गुजरात में उभरते खिलाड़ियों को उत्तरोत्तर बढ़ते स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा प्रशिक्षण एवं अत्याधुनिक सुविधाएँ दी जा रही होने के बारे में विस्तार से भूमिका रखी। मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि राज्य के 32 जिलों में अनिवासी (नॉन–रेजीडेंशियल) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 24 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा जिला स्तरीय खेल विद्यालयों (डीएलएसएस) के माध्यम से उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि 200 से अधिक खिलाड़ी यहाँ आर्चरी का प्रशिक्षण लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हमारी मंशा है

कपड़ा बाजार में विवाद समाधान के लिए फोस्टा की मध्यस्थता अनिवार्य

व्यापारियों को बिल बुक और चालान पर फोस्टा आर्बिट्रेशन लिखने के निर्देश

सूरत। सूरत के कपड़ा बाजार में व्यापार संबंधी विवादों के समाधान के लिए अब फोस्टा आर्बिट्रेशन (FOSTA Arbitration) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। कपड़ा बाजार संगठन फोस्टा ने मध्यस्थता अधिनियम के तहत विवादों का निपटारा करने की पहल की है और व्यापारियों को अपनी बिल बुक और चालान पर फोस्टा आर्बिट्रेशन स्पष्ट रूप से लिखने के निर्देश दिए हैं।

फोस्टा के अध्यक्ष कैलाश हकीम ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि अब व्यापारियों के सामने आने वाली किसी भी भुगतान संबंधी समस्या का समाधान मध्यस्थता अधिनियम के तहत पफोस्टा के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाजार क्षेत्र में धोखाधड़ी और भुगतान में देरी जैसी शिकायतें अक्सर मिलती हैं, जिनका समाधान पहले फोन या पुलिस की मदद से करने का

प्रयास किया जाता थाहालांकि, फोस्टा का नया संविधान तैयार होने के बाद अब मध्यस्थता अधिनियम लागू कर दिया गया है। इसके तहत व्यापारियों की भुगतान संबंधी समस्याओं का आधिकारिक और कानूनी रूप से समाधान किया जा सकेगा।फोस्टा ने सभी व्यापारियों को निर्देशित किया है कि वे अपनी बिल बुक और चालान पर फोस्टा मध्यस्थता की मुहर इस प्रकार लगाएं कि वह आसानी से पढ़ी जा सके। इसके साथ ही, नई बिल बुक और चालान में भी इसे छपवाने के लिए कहा गया है, ताकि भविष्य में भुगतान संबंधी किसी भी समस्या का समाधान मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा सके।कैलाश हकीम ने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे इस निर्देश का पालन करें ताकि व्यापारिक विवादों का त्वरित और न्यायसंगत निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।

मेरा बूथ, सबसे मजबूत मेरा बूथ, मेरा परिवार

भाजपा का स्थापना दिवस 167- पश्चिम विधानसभा सदस्यों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया

सूरत। रविवार 06 अप्रैल 2025 को रामनवमी के पावन अवसर पर एवं भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर 167 - सूरत पश्चिम विधानसभा बूथ क्रमांक - 172 का कार्यक्रम 1100 करोड़ श्री राम नाम मंत्र मंदिर, विश्व शांति श्री राम स्तम्भभूमि, श्री रामजी मंदिर, गुरु राम पावनभूमि के पास, एक्वेरियम के पीछे, केबल ब्रिज के पास, अडाजण सूरत में सम्पन्न हुआ।कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई।इस अवसर पर गुजरात सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेशभाई मोदी, प्रमुख बूथ कार्यकर्ता, 167 - सूरत पश्चिम विधानसभा प्रभारी प्रवीणभाई पटेल, पूर्व सैनिक, जनसंघ कार्यकर्ता वासुदेवभाई अग्रवाल, पूर्व नगरसेवक, पूर्व वार्ड अध्यक्ष-महासचिव, 167 - सूरत पश्चिम विधानसभा भाजपा परिवार, स्थानीय नेता, देवतुल्य कार्यकर्ता और शुभचिंतक बड़ी संख्या में शामिल हुए।इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गुजरात सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक पूर्णेशभाई मोदी थे। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया है तथा राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर विकास की राजनीति का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने तथा भारत माता को सर्वोच्च गौरव पर ले जाने के दृढ़ संकल्प के साथ उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। और राष्ट्र सेवा में समर्पित करोड़ों देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी।बूथ के वरिष्ठ नेता श्री दोलतभाई नायक (दोलत काका) को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व चहुंमुखी विकास किया है और आने वाले समय में सभी भाजपा कार्यकर्ता इसे एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे।

भाजपा स्थापना दिवस पर मोटा वराछा में कार्यकर्ताओं ने किया जनसंपर्क अभियान

बूथ स्तर पर पार्टी ध्वज फहराए, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की दी जानकारी

सूरत। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सूरत महानगर भाजपा बक्शी पंच मोर्चा द्वारा ओलपाड विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2, बूथ क्रमांक 370 (मोटा वराछा माली फलिया) में विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व भाजपा बक्शी पंच मोर्चा के अध्यक्ष अनिमेष भाई माली ने किया। कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की, भाजपा के झंडे फहराए और केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई। जनसंपर्क कार्यक्रम में करसनभाई गोंदलिया, गौरवभाई इटालिया, नगरसेविका भावनाबेन सोलंकी, रमेशभाई पटेल समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर अनिमेष माली ने कहा कि भाजपा ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को आधार बनाकर जनसेवा की है। स्थापना दिवस पर यह जनसंपर्क अभियान आम लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है।

विश्व प्रसिद्ध बीएपीएस रामनवमी हिंदू मंदिर, अबू धाबी में भव्यता के साथ मनाई गई

सूरत। रामनवमी के साथ-साथ श्री स्वामीनारायण जयंती के अवसर पर अबू धाबी मंदिर समेत दुनिया भर के ~~क्कक~~ मंदिरों में भव्य समारोह विश्व भर में सद्भाव के प्रतीक और सनातन हिंदू धर्म के गौरव बीएपीएस हिंदू मंदिर, अबू धाबी में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया।

अबू धाबी मंदिर के मुख्य पीठासीन संत, वेन. ब्रह्मविहारी स्वामी के अनुसार आज रामनवमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े।

यू. ए. ई. नगर में रहने वाले हजारों श्रद्धालुओं एवं भावी श्रद्धालुओं के लिए यह एक अमूल्य अवसर था, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक राम भजनों एवं रात्रि 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव आरती का लाभ उठाया।

गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बने गंगा घाट पर बीएपीएस के युवा कलाकारों ने विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भगवान श्री राम के दिव्य और प्रेरक जीवन चरित्रों की रोमांचक प्रस्तुति दी।

सूरत में तेलुगु समुदाय ने पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया सीता राम कल्याण महोत्सव

रामनवमी पर भगवान राम और सीता के विवाह की रस्में निभाई, शोभायात्रा व महाप्रसाद में उमड़ा जनसैलाब

सूरत। रामनवमी के पावन अवसर पर सूरत के तेलुगु समुदाय द्वारा सीता राम कल्याण महोत्सव बड़े ही श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया। इस दौरान भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह की वैदिक विधियों के अनुसार रस्में निभाई गईं, और शोभायात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

सूरत में तेलुगु समाज के अग्रणी रापोलु बुच्चिरामोलु ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि दक्षिण भारत में हर साल रामनवमी के दिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम और सीता का विवाह सम्पन्न होता है, लेकिन इस दिन उत्तर भारत में श्री राम का जन्मोत्सव श्री राम नवमी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है।

सूरत का यह आयोजन तेलंगाना के बद्राचलम मंदिर की परंपरा पर आधारित था, जहां हर वर्ष रामनवमी के दिन श्रीराम और सीता का विवाह सम्पन्न कराया जाता है। सूरत में भी तेलुगु बहुल इलाकों जैसे मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर, प्रतापनगर, कुंभारिया, कल्पना, कैलाश नगर, गोडादरा, बालाजी नगर, भाग्यनगर आदि में इस धार्मिक उत्सव को उत्साहपूर्वक मनाया गया।

समारोह में भगवान श्रीराम और माता सीता की मूर्तियों का मंडप में पारंपरिक विवाह कराया गया। तेलुगु समुदाय के एक दंपति ने रामजी और दूसरे ने सीता माता की मूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए मंगल फेरे लिए। विवाह की सभी वैदिक रस्में निभाई गईं और ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विवाह सम्पन्न किया गया। इसके पश्चात भगवान की बारात निकाली गई, जिसका आरती, अगरबत्ती और जल से स्वागत किया गया।

श्री माधव गौशाला द्वारा उधना क्षेत्र में भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया

आज श्री रामनवमी के अवसर पर सांस्कृतिक संरक्षण समिति द्वारा प्रबंधित श्री माधव गौशाला द्वारा उधना क्षेत्र में भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। अनेक देवी-देवताओं की झांकियां प्रदर्शित की गईं। इस जुलूस में लगभग 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने भी भाग लिया। मुख्य आकर्षण लाजिम नृत्य की सुंदर कला और अघोरी बाबा, बाहुबली हनुमानजी और शंकरजी की झांकी के साथ-साथ महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मी बाई, अयोध्या राम मंदिर में विराजमान रामलला और अनेक महापुरुषों एवं ऋषियों की झांकियां भी थीं। संगठन के अध्यक्ष श्री आशीष सूर्यवंशी ने आगे कहा कि रामनवमी के अवसर पर उधा क्षेत्र राम नाम से गूंज उठा। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा।

2024-25: सॉफ्ट स्किल्स विकास कार्यक्रमों में कृषि विश्वविद्यालय का नया मील का पत्थर

इस वर्ष 179 घंटों के 53 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 3808 छात्रों को रोजगार योग्य बनाया

इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में हार्ड-टेक्निकल कौशल के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स का विकास भी बहुत जरूरी है : डॉ. जेड.पी. पटेल

नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति डॉ जेड पी पटेल के सशक्त नेतृत्व, अनुसंधान निदेशक डॉ तैमूर आर अहलावत के मार्गदर्शन और जीवंत छात्र कल्याण निदेशक प्रोफेसर जयमिन आर. नायक के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट एवं काउंसलिंग प्रमुख डॉ मेहुल जी. ठक्कर के समर्पित प्रयासों से विश्वविद्यालय ने 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में सॉफ्ट स्किल्स विकास कार्यक्रमों में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। विश्वविद्यालय के 6 पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और 8 डिग्री कॉलेजों के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्रों को पेशेवर संवारने और रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स में पारंगत करने के लिए इस वर्ष पिछले 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3808 छात्रों को कुल 179 घंटों के 53 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से घर पर ही प्रशिक्षित किया जा रहा है मानव संसाधन प्रबंधन के प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के सबसे लंबे समय तक कार्यरत प्लेसमेंट और काउंसलिंग प्रमुख और प्रसिद्ध प्रेरणा गुरु डॉ मेहुल जी। ठक्कर के अनुसार, कुशल और अच्छी तरह से प्रशिक्षित युवा देश की जरूरत है और कुलपति डॉ। एकीकृत लोगों के प्रबंधन में विश्वास करते हैं। ज़ेड.पी. पटेल ने हमेशा छात्र-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन को प्रोत्साहित किया है। छात्र कल्याण निदेशक प्रोफेसर जयमिन आर., जो विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट और परामर्श प्रकोष्ठ के मार्गदर्शक प्रमुख हैं। नायक ने इस उपलब्धि का श्रेय माननीय कुलपति के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया और कहा कि कैम्पस प्लेसमेंट प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को नामी कम्पनियों में आकर्षक वेतन पर नौकरी मिलने के पीछे; विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और इस प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान किया जाने वाला परिणामोन्मुखी प्रशिक्षण

इसका प्रमुख हिस्सा है। अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त प्रशिक्षक डॉ. मेहुल जी. ठक्कर द्वारा प्रदत्त इस प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी 21वीं सदी के लिए प्रासंगिक एवं सुसंगत कौशल विकसित कर, स्वयं को कॉरपोरेट अनुकूल बनाकर तथा घर बैठे ही रोजगार के अवसर प्राप्त कर विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ा रहे हैं। डॉ., एक योग्य कृषि वैज्ञानिक एवं कुलपति, जिन्हें दुनिया भर में मैन ऑफ फ्रूट फ्लाई के नाम से जाना जाता है और जिनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल करता रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती पटेल ने कहा कि सक्षम एवं कुशल युवा ही समाज, देश एवं विश्व का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बाद रोजगार योग्य बनाने अर्थात आकर्षक वेतन के साथ रोजगार प्राप्त करने के लिए हार्ड स्किल्स अर्थात तकनीकी क्षमताओं में दक्षता के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स का विकास भी अत्यंत आवश्यक है। वाइब्रेंट स्टूडेंट वेलफेयर के निदेशक प्रोफेसर जयमिन आर नायक और विश्वविद्यालय के इन-हाउस ट्रेनर डॉ मेहुल जी के सहयोग से वे 24*7*365 अप्रोच के साथ लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने ठक्कर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जो छात्र इस साल जुलाई-2025 में पास होंगे, उनके लिए अक्टूबर-2024 से सुमिन्तर इंडिया ऑर्गेनिक्स जैसी नामी कंपनियों के साथ कैंपस इंटरव्यू की शुरुआत होगी; प्लेसमेंट प्रक्रिया-2025 में अब तक आयोजित कुल 39 कैम्पस साक्षात्कारों के साथ आकर्षक वेतन के साथ नौकरी के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के उज्ज्वल कैरियर के सपने साकार हो रहे हैं। इसके लिए छात्र कल्याण निदेशक कार्यालय के सभी कर्मचारियों को बधाई; उज्ज्वल कैरियर के निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के माध्यम से छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए अब तक इस विश्वविद्यालय के 14 कॉलेजों के 27690 छात्रों को 1770 घंटों के कुल 384 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करके एक महान योगदान देने के अलावा; 850 से अधिक कैम्पस साक्षात्कार आयोजित कर 2000 से अधिक विद्यार्थियों को नौकरी दिलाने वाले एचआरडी विशेषज्ञ डॉ. मेहुल जी. ठक्कर के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की गई। इसके साथ ही, उन्होंने कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए सक्षम मानव संसाधन तैयार करके कुशल भारत, कुशल भारत के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के सपने को भी साकार किया है।

OWNER, PRINTER, PUBISHER & EDITOR-KULKARNI VINOD SUDHAKAR, PRINTED AT UNNATI PRINTERS, 29 NATIONAL IND. SOC, OLD UN NAKA, SURAT-NAVSARI MAIN ROAD, SURAT-394210, PUBLISHED AT-245, AASHIRWAD TOWN SHIP-1, BAMROLI ROAD, UDHANA, DIST-SURAT, GUJARAT